



टैक्स, हेल्थ, रक्षा और महिलाओं पर फोकस

नई दिल्ली, 1 फरवरी. बजट में इस बार आम आदमी की जरूरतों से जुड़े सेक्टर पर बड़ा जोर दिखा. हेल्थकेयर में दवाओं पर इयूटी छूट, एजुकेशन में कंटेंट क्रिएटर लैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईस्पीड रेल कॉरिडोर, किसानों के लाभ जैसी बड़ी घोषणाएं की गई हैं.

सरकार ने साफ संकेत दिया कि विकास की रफ्तार, लोगों की क्षमता और हर क्षेत्र की भागीदारी—इन तीन विजन पर आगे बढ़ा जाएगा. साथ ही टैक्स स्लैब स्थिर रखते हुए रिवाइज्ड रिटर्न की समय सीमा बढ़ाई गई. वित्त मंत्री ने बजट में 7 बड़ी घोषणाएं करते हुए हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी. कैसर की 17 दवाओं और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयों को इयूटी फ्री किया गया. 15 हजार स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट

पांच साल में 20 नए राष्ट्रीय बनेंगे जलमार्ग

रेल-जलमार्ग और ग्रीन ट्रांसपोर्ट सेक्टर- 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे शहरों के बीच 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे. ये मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी के बीच बनेंगे. अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनेंगे. बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाएं विकसित की जाएगी.

फॉर्सस के आधुनिकीकरण पर 2.19 लाख खर्च होंगे

डिफेंस बजट के लिए 7.85 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसमें पिछले साल के 6.81 लाख करोड़ के मुकाबले 15.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. कुल रकम में से सैन्य बलों के आधुनिकीकरण पर 2.19 लाख खर्च होंगे. पिछले साल यह 1.80 लाख करोड़ था. विमान और एयरो इंजन डेवलपमेंट के लिए 64 हजार करोड़ और नौसेना बेड़े के लिए 25 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं. पेंशन के लिए 1.71 लाख करोड़ अलग रखे गए हैं. बैटरी बनाने की मशीनों पर टैक्स छूट बढ़ी सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी बनाने वाली मशीनों पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया.

एयरक्राफ्ट मॉटेनेंस सस्ता- पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी हटी

नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए एयरक्राफ्ट बनाने में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों और कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है. डिफेंस सेक्टर में भी एयरक्राफ्ट के मॉटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए मंगाए जाने वाले कच्चे माल पर अब टैक्स नहीं देना होगा. आयुर्वेद- भारत को ग्लोबल बायो फार्मा मैनुफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाने का एलान किया गया है. आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनाई जाएंगी. भारत को ग्लोबल लेवल पर बायोफार्मा प्रोडक्ट के उत्पादन का हब बनाया जाएगा. गर्ल्स एजुकेशन- करीब 800 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल, हर जिले में एक हॉस्टल देश में 789 जिले हैं. हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का एलान किया गया है. गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) शिक्षा को विशेष प्राथमिकता देने की बात कही. महिलाएं- लखपति दीदी मॉडल पर रोजगार और आय बढ़ाने की स्कीम लखपति दीदी की तर्ज पर महिला स्वयं सहायता समूह की उद्यमी महिलाओं के लिए एएसएचई-मार्ट (शी-मार्ट) बनाए जाएंगे. इन दुकानों को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के समुदाय ही चलाएंगे. यहां महिलाओं के बनाए खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प, कपड़े और स्थानीय उत्पाद सीधे बेचे जाएंगे. इससे बिलीयों की भूमिका कम होगी और महिलाओं को अपने कारोबार पर मालिकाना हक मिलेगा.



बजट की उत्पत्ति से लेकर इतिहास तक...



चमड़े के झोले से 'बजट'

'बजट' शब्द सुनते ही दिमाग में आय-व्यय, टैक्स और सरकारी योजनाओं की तस्वीर उभरती है. लेकिन इसकी जड़ें एक छोटे से चमड़े के थैले से जुड़ी हैं. फ्रेंच शब्द 'बोगेटे' से निकला यह शब्द लैटिन 'बुल्गा' और सैल्टिक 'ब्लोग' से भी संबंध रखता है. समय के साथ यह थैला सिर्फ सामान रखने का साधन नहीं रहा, बल्कि सरकारी लेखा-जोखा और वित्तीय पारदर्शिता का प्रतीक बन गया. यहीं से 'बजट' का आधुनिक अर्थ आकार लेने लगा. 17वीं-18वीं सदी के इंग्लैंड में वित्त मंत्री जरूरी दस्तावेज चमड़े के बैग में रखकर संसद जाते थे.



1860 में पेश हुआ था

देश का पहला यूनिवर्सल बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया. उस समय देश ब्रिटिश शासन के अधीन था. यह बजट ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जेम्स विल्सन ने पेश किया था. 1857 की क्रांति के बाद भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी. उसी घाटे को संभालने और सरकारी खर्चों पर कंट्रोल करने के लिए पहली बार बजट का कॉन्सेप्ट लाया गया. यहीं से भारत में सिस्टमेटिक फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत होती है. बता दें भारत के बजट इतिहास का सबसे लंबा भाषण 2020 में देखने को मिला था. यह भाषण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया. जो 2 घंटे 40 मिनट तक चला. लगातार पढ़ते-पढ़ते उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें भाषण बीच में रोकना पड़ा. इसके बाद बाकी हिस्सा संसद में लिखित रूप में पेश किया गया.

सबसे छोटा बजट भाषण

जहां एक तरफ लंबा भाषण रिकॉर्ड बना. वहीं, भारत ने बेहद छोटा बजट भाषणा भी देखा. 1977 में मोरारजी देसाई की कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर रहे हीरूभाई मुल्जीभाई पटेल ने सिर्फ 800 शब्दों में बजट भाषण खत्म कर दिया था. यह आज तक का सबसे छोटा और संक्षिप्त बजट भाषण माना जाता है.

रेल बजट अलग होता था

भारत में रेल बजट पहले अलग से पेश किया जाता था. 1924 से 2016 तक रेलवे का बजट यूनिवर्सल बजट से अलग ही रहा. 2017 में मोदी सरकार ने इसे केंद्रीय बजट में शामिल कर दिया, ताकि फाइनेंशियल प्लानिंग और पॉलिसी लागू करने की प्रोसेस आसान हो सके. रेल बजट में रैकडों नई ट्रेनों की घोषणा की जाती थी. इसके अलावा कई ट्रेनों के रूट का विस्तार भी किया जाता था. वहीं 1950 तक बजट की प्रिंटिंग राष्ट्रपति भवन में हुआ करता थी, लेकिन उसी साल बजट लोक की घटना ने यह प्रक्रिया बदल गई. इस लोक के कारण तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई को अपने पद से रिजाइन देना पड़ा. इसके बाद सरकार ने प्रिंटिंग मिंटो रोड प्रेस और बाद में नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में शिफ्ट कर दी.

आयकर की शुरुआत

ब्रिटिश इंडिया के पहले बजट से ही आयकर की शुरुआत हो गई थी. यानी 1860 में इस सिस्टम को लाया गया. इसे शुरुआत में अस्थायी व्यवस्था माना गया, लेकिन धीरे-धीरे यह सरकार की इनकम का परमानेंट पिलर बन गया. इसके अलावा भारत में सबसे ज्यादा केंद्रीय बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम पर है. उन्होंने अलग-अलग कार्यकाल में 10 बार बजट पेश किए.

इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए 40 हजार करोड़ देंगे

1000 मान्यता प्राप्त क्लीनिकल साइट्स बनाई जाएंगी, जहां साइंटिफिक रिसर्च हो सकेगी. सेमीकंडक्टर मिशन - प्रोडक्शन और इंडियन आईपी बनाने, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रावधान किया गया है. इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए 40 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. रेंजर अर्थ मटेरियल के लिए ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड फेसिलिटी बनाने की पहल की गई है. इसके लिए डेडिकेटेड मिनरल पार्क बनाए जाएंगे. हाई टेक टूल रूम दो लोकेशन पर हाई प्रेसिजन कंपोनेंट्स बनाने के लिए - इसके तहत टनल बोरिंग मशीन से लेकर मल्टी स्टोरीज में फायर फाइटिंग सिस्टम तक बनेंगे.

यहां से लाया जाएगा रुपया

वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में आमदनी और खर्च का ब्योरा एक रुपये के आधार पर इस प्रकार है.

सरकार की कमाई, कर्ज और घाटे का पूरा हिसाब

सरकारी कर्ज में कमी लाने का लक्ष्य सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030-31 तक देश का कुल कर्ज, जीडीपी के 50 प्रतिशत के बराबर लाया जाए. 2025-26 में यह कर्ज 56.1 फीसदी था, जो अब 2026-27 में घटकर 55.6 फीसदी रहने का अनुमान है. यह कर्ज कम होगा तो सरकार को ब्याज कम देना पड़ेगा. जिससे वो पैसा स्कूल, अस्पताल और सड़कों पर खर्च हो सकेगा. राजकोषीय घाटा पिछली बार से कम हुआ राजकोषीय घाटा मतलब सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर. सरकार ने कहा है कि वह घाटे को जीडीपी के 4.5 फीसदी से नीचे ले आई है. 2025-26 में यह घाटा 4.4 फीसदी रहा। अगले साल (2026-27) के लिए इसे और घटाकर 4.3 फीसदी करने का लक्ष्य है. पिछले साल (2025-26) का हिसाब किताब सरकार की कुल कमाई 34 लाख करोड़ रही. इसमें से 26.7 लाख करोड़ टैक्स से आए. वहीं कुल खर्च 49.6 लाख करोड़ रहा. पुर्जीगत खर्च यानी लगभग 11 लाख करोड़ नए ब्रिज, हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च हुआ. अगले साल (2026-27) का बजट प्लान सरकार ने 36.5 लाख करोड़ कुल कमाई का अनुमान है.

पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में बौद्ध सर्किट

पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में बौद्ध सर्किट बनाए जाएंगे. मेडिकल टूरिज्म - भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के तौर पर बढ़ावा देने के लिए, मैं राज्यों को देश में 5 रीजनल हब स्थापित करने में मदद करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव. वहीं 20 लाख रुपए से कम की विदेश में इम्यूनेवेल प्रॉपर्टी डिस्कलोज करने पर पेनाल्टी नहीं.

18 प्रतिशत निगम कर से लाया जाएगा रुपया

15 प्रतिशत जीएसटी और अन्य करों से जुटाई जाएगी राशि

20 प्रतिशत ऋण भुगतान

11 प्रतिशत रक्षा के लिए

17 फीसदी केंद्रीय योजना

10 प्रतिशत गैर कर राजस्व से और गैर ऋण पूंजी प्राप्ति से 2 प्रतिशत

06 प्रतिशत प्रमुख सब्सिडी

02 प्रतिशत सिविल पेंशन

07 फीसदी अन्य व्यय

07 प्रतिशत वित्त आयोग और अन्य हस्तंतरण भी किया जाएगा

- ▶ टैक्स अनुमान - 34 लाख करोड़ का है.
- ▶ कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.2 लाख करोड़ व बजट एस्टीमेट 36.5 लाख करोड़ का है.
- ▶ न्यू इनकम टैक्स एक्ट आगामी एक अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा.
- ▶ सिंपलीफाइड फॉर्म रीडिजाइन किए हैं, आम आदमी भर सके.
- ▶ टैक्स अनुमान - 34 लाख करोड़ का है.
- ▶ कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.2 लाख करोड़ व बजट एस्टीमेट 36.5 लाख करोड़ का है.
- ▶ न्यू इनकम टैक्स एक्ट आगामी एक अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा.
- ▶ सिंपलीफाइड फॉर्म रीडिजाइन किए हैं, आम आदमी भर सके.
- ▶ मोटर एक्सीडेंट वलैम की रकम को इनकम टैक्स से छूट दी है.
- ▶ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर 5 प्रतिशत की जगह 2 प्रतिशत टैक्स किया गया है.
- ▶ एमर्गेंसी हायरिंग सर्विस पर 1 से 2 फीसदी टैक्स होगा.
- ▶ राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 4.5 परसेंट से नीचे रखने का लक्ष्य



मेगा टैक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे

नेशनल फाइबर स्कीम, मेन मेड फाइबर, एडवांस्ड फाइबर, नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगरों को प्रोत्साहन और मदद मिलेगी.

एकेडमिक इंस्टीट्यूट से तकनीकी मदद संभव होगी. मेगा टैक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे

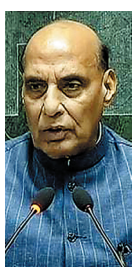
पक्ष-विपक्ष की प्रतिक्रिया

हॉस्टल-इंफ्रा पर सियासी बयानबाजी, बजट बना विकास बनाम सवालों का मुद्दा

जनभावनाओं वाला बजट

राजनाथ

रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए आवंटित होने पर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार जताया. उन्होंने कहा कि यह जनभावनाओं और जन-अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट है.



लोक-कल्याण वाला बजट

जेपी नड्डा

इस बार का पेश किया बजट को लोक-कल्याणकारी, सर्वसमावेशी और विकसित भारत के लक्ष्य के प्रति संकल्पित देश के आर्थिक विकास को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक है.



बजट सुशासन व विकसित

नितिन नबीन

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कर्तव्य भवन में बना और कर्तव्य पथ पर चलने वाला बजट है. यह देश के प्रति सरकार की जिम्मेदारी, दूरदर्शिता और जनकल्याणकारी सोच को स्पष्ट रूप से दर्शाता है.



आकांक्षाओं को पूरा किया

योगी आदित्यनाथ

देशवासियों की आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक यह बजट है, जिसमें मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि, रेल कॉरिडोर, जैसे ठोस प्रावधान किए गए हैं.



विकास पर केंद्रित बजट

किरेन

बजट में कोई राजनीतिक बात नहीं कही गयी. यह पूरी तरह विकास पर केंद्रित है. विकसित भारत के लिए पीएम ने जो 'रिफार्म एक्सप्रेस' चलाया गया है, उसी की झलक इसमें है।



बजट पांच प्रतिशत के लिए

अखिलेश

भाजपा सरकार से जनता को कोई उम्मीद नहीं है. तो उसके बजट से भी क्या अपेक्षा की जा सकती है. हर बजट 1/20 का बजट होता है, क्योंकि यह केवल 5 प्रतिशत लोगों के हित के लिए होता है.



बिना नौकरी के ग्रोथ नहीं

शशि थरूर

बिना नौकरी के ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है. हम इस बात को जानने के लिए उत्सुक हैं कि वित्त मंत्री किस तरह की स्कीम्स लाती हैं, जिससे युवाओं को नौकरियां मिलेगी.



संकल्पों की सिद्धि का बजट

ब्रजेश पाठक

यह बजट करोड़ों देशवासियों की आशाओं, और संकल्पों की सिद्धि का बजट है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को मजबूती प्रदान करेगा.

